

CORPORATE OFFICE

Delhi Office

706 Ground Floor Dr. Mukherjee
Nagar Near Batra Cinema Delhi -
110009

Noida Office

Basement C-32 Noida Sector-2
Uttar Pradesh 201301



 Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojniaas.com

website : www.yojniaas.com
Contact No. : +91 8595390705

दिनांक: 1 फरवरी 2024

भारत - फ्रांस रणनीतिक साझेदारी

स्रोत - द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन - अंतर्राष्ट्रीय संबंध , भारत - फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्षितिज 2047, COP 33, जी20 शिखर सम्मेलन ।

खबरों में क्यों ?



- भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुएल मैक्रॉन ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत का राजकीय दौरा किया। यह राष्ट्रपति मैक्रॉन की भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है और गणतंत्र दिवस के सम्माननीय अतिथि के रूप में किसी फ्रांसीसी नेता की छठी यात्रा है।
- भारत और फ्रांस इस साल अपने आपसी रणनीतिक साझेदारी का 25वां वर्षगांठ मना रहा है। फ्रांस पश्चिमी दुनिया में भारत का पहला रणनीतिक साझेदार देश है। इतना ही नहीं, फ्रांस के लिए भारत पहला गैर-यूरोपीय भागीदार भी है। ऐसे में मैक्रॉन को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना महत्वपूर्ण है। यह पीएम मोदी की दोस्ती का एक पारस्परिक संकेत भी है। यह भी बड़ी बात है कि साल 2023 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन ने कम से कम एक दर्जन बार मुलाकात की थी। इनमें से कई मुलाकातें द्विपक्षीय और कई बड़े-बड़े मल्टीनेशनल प्रोग्राम के दौरान हुई थीं। पिछले साल भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैक्रॉन भारत भी आए थे।
- फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत पहुंचे हैं। उनका जयपुर में महाराजा शैली में स्वागत किया गया। जंतर-मंतर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मैक्रॉन ने पीएम मोदी के साथ पिक सिटी में एक रोड शो में हिस्सा लिया। पीएम मोदी और मैक्रॉन जब भी मिलते हैं, तब दोनों नेता एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाते हैं। यह प्रतीकात्मक है, जो बताता है कि भारत और फ्रांस हर संभव क्षेत्र में सहयोग करते हुए एक दूसरे को मजबूती से गले लगा रहे हैं। भारत-फ्रांस की 'दोस्ती' खास भी है। यह भी एक कारण है कि फ्रांसीसी नागरिक और राष्ट्रपति मैक्रॉन भारत के सबसे करीबी मित्रों में शामिल हैं।

- भारत के गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रपति मैक्रॉन की यात्रा 14 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस पर सम्मानित अतिथि के रूप में प्रधान मंत्री की फ्रांस की ऐतिहासिक यात्रा के बाद हुई, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने एक महत्वाकांक्षी योजना क्षितिज 2047 का अनावरण किया। भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष के लिए क्षितिज 2047, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक 'मील का पत्थर' है। दोनों नेताओं का लगातार राष्ट्रीय दिवसों पर सम्मानित अतिथि बनना अभूतपूर्व है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं वर्षगांठ का जश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस में फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति की उपस्थिति लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है, और दोनों देशों की आपसी दोस्ती की प्रगाढ़ता और आपसी रणनीतिक साझेदारी की ताकत के लिए एक मजबूत स्तंभ है।
- राष्ट्रपति मैक्रॉन के साथ एक मजबूत उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें सशस्त्र बलों, संस्कृति, यूरोपीय और विदेशी मामलों के मंत्रियों के साथ-साथ फ्रांसीसी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सीईओ और उद्योग के नेता शामिल थे। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के तीन विमानों ने कर्तव्य पथ पर भारतीय वायु सेना के विमान के साथ उड़ान भरी, और एक फ्रांसीसी सैन्य दल ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया।
- 1998 में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के बाद से, भारत और फ्रांस ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता में मजबूत विश्वास के आधार पर असाधारण विश्वास और आत्मविश्वास, स्थिरता और ताकत की साझेदारी विकसित की है। और रणनीतिक स्वायत्तता, एक बहुध्रुवीय दुनिया के लिए एक साझा प्रतिबद्धता, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति। प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन ने अपने दृष्टिकोण की पुष्टि की कि भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी उनकी अर्थव्यवस्थाओं में समृद्धि और लचीलापन बनाने में मदद कर सकती है, अपने देशों की सुरक्षा को आगे बढ़ा सकती है, और ग्रह के लिए अधिक टिकाऊ और स्वस्थ भविष्य, वैश्विक चुनौतियों के लिए समाधान ढूंढ सकती है, पुनर्जीवित कर सकती है। बहुपक्षवाद और एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अधिक एकजुट और एकजुट दुनिया बनाने में मदद करता है।
- भारत के प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन ने **क्षितिज 2047** और जुलाई 2023 शिखर सम्मेलन के अन्य दस्तावेजों में उल्लिखित द्विपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की सराहना की और संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के तीन व्यापक स्तंभों – शांति और समृद्धि के लिए साझेदारी, ग्रह के लिए साझेदारी और लोगों के लिए साझेदारी – में इसे और तेज करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने दीर्घकालिक वैश्विक चुनौतियों और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विकास पर व्यापक चर्चा की, और अपने समान हितों और दृष्टिकोणों से प्रेरित होकर, बहुपक्षीय पहल और संस्थानों के माध्यम से अपने वैश्विक और क्षेत्रीय जुड़ाव को तेज करने पर सहमति व्यक्त की।
- राष्ट्रपति मैक्रॉन ने भारत की सफल जी20 नेताओं की दिल्ली घोषणा में भारत की अध्यक्षता के लिए प्रधान मंत्री मोदी को उनके नेतृत्व के लिए बधाई दी, जो अपने सुचारु संचालन, अपने महत्वाकांक्षी परिणामों और नई पहलों और आम सहमति की उपलब्धि में **"एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य"** की थीम पर खरा उतरा। उन्होंने G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने का स्वागत किया और कहा कि इससे मंच के समावेशी और प्रतिनिधि चरित्र में वृद्धि हुई है। वे इस बात पर सहमत हुए कि दिल्ली में प्राप्त सर्वसम्मति ने समावेशी वैश्विक एजेंडा और 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए ब्राजील का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में G20 को मजबूत किया है।
- भारत और फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण की परस्पर जुड़ी चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधान मंत्री मोदी ने 2023 में राष्ट्रपति मैक्रॉन की अंतरराष्ट्रीय पहल की सराहना की, जिसमें जून में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन भी शामिल था, जिसके कारण लोगों और ग्रह के लिए पेरिस समझौता हुआ और पेरिस में वन प्लैनेट – पोलर शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों नेता 2025 में नीस में आयोजित होने वाले तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (यूएनओसी3) के लिए उत्सुक थे। उन्होंने दुबई में सीओपी28 के सफल आयोजन में यूएई के नेतृत्व की सराहना की और सीओपी के नतीजे, विशेष रूप से यूएई की सहमति का स्वागत किया, जिसमें निर्णय शामिल थे। पहले वैश्विक स्टॉकटेक पर, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य पर रूपरेखा, जस्ट ट्रांज़िशन पर कार्य कार्यक्रम और हानि और क्षति का जवाब देने के लिए एक फंड सहित फंडिंग व्यवस्था के संचालन पर। दोनों नेताओं ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ अपने अगले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में आगे आने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

- राष्ट्रपति मैक्रोन ने 2028 में **COP 33** की मेजबानी के भारत के प्रस्ताव की सराहना की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत की उम्मीदवारी के लिए फ्रांस के समर्थन की भी पुष्टि की। भारत की IEA सदस्यता पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और ऊर्जा संक्रमण की स्थिरता और विकास में योगदान देगी। बहुपक्षीय ढांचे पर विशेष ध्यान देने के साथ राजनीतिक मामलों और महासागरों, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रदूषण और डिजिटल जैसे अन्य वैश्विक मुद्दों पर परामर्श आयोजित करने के लिए, दोनों नेता वैश्विक मुद्दों पर एक व्यापक वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि की स्थापना के लिए बातचीत पर इस वर्ष एक महत्वाकांक्षी परिणाम के लिए आम सहमति बनाने का आह्वान किया। फ्रांस और भारत संयुक्त महत्वाकांक्षा बनाने और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए रियो कन्वेंशन के तीन सीओपी (जलवायु, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण) के संदर्भ में भी अपना सहयोग बढ़ाएंगे। यूएनओसी 2025 की तैयारी के संदर्भ में, फ्रांस ने "मर्केटर" पहल में शामिल होने के भारत के फैसले का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य महासागर का एक वैश्विक 'डिजिटल ट्रिन' बनाना है। अंत में, राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत सरकार को वैश्विक मंच में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। **बिल्डिंग्स एंड क्लाइमेट", फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा सह-आयोजित है, जो 7 और 8 मार्च 2024 को पेरिस में होगा।**
- प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर, दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। नेताओं ने अपने-अपने संप्रभु और रणनीतिक हितों के लिए क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित और शांतिपूर्ण इंडो-पैसिफिक और उससे आगे की प्रगति के लिए क्षेत्र में अपनी साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। इंडो-पैसिफिक के लिए व्यापक रोडमैप का उल्लेख करते हुए, जिसे जुलाई 2023 में अंतिम रूप दिया गया था, उन्होंने क्षेत्र में अपनी भागीदारी की विस्तारित प्रकृति पर संतोष व्यक्त किया।
- रक्षा और सुरक्षा साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत-फ्रांस साझेदारी की आधारशिला रही है, जिसमें विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में द्विपक्षीय, बहुराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और संस्थागत पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वे 2020 और 2022 में फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र ला रीयूनियन से किए गए संयुक्त निगरानी मिशनों के आधार पर, दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में अपने सहयोग को तेज करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने भारत के समुद्री पड़ोस में उन बातचीत के विस्तार का भी स्वागत किया। ये बातचीत संचार के रणनीतिक समुद्री मार्गों के प्रतिभूतिकरण में सकारात्मक योगदान दे सकती है। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता में प्रगति और क्षेत्र में मित्र देशों के लिए रक्षा उपकरणों के निर्माण और निर्यात के लिए भारत को आधार के रूप में उपयोग करने के लिए विशिष्ट अवसरों की पहचान का स्वागत किया।
- दोनों नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित करने, यूई के साथ इसे गहरा करने और क्षेत्र में नए सहयोग की खोज करने की भी प्रतिबद्धता जताई।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास, मानव कल्याण, पर्यावरणीय स्थिरता, लचीले बुनियादी ढांचे, नवाचार और कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए संयुक्त और बहुपक्षीय पहल के महत्व को ध्यान में रखते हुए, दोनों नेताओं ने अपनी सरकारों से ठोस परियोजनाओं की पहचान करने को कहा। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में विकसित की जा रही हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने की सुविधा के लिए **इंडो-पैसिफिक त्रिकोणीय विकास सहयोग कोष** को शीघ्र शुरू करने का आह्वान किया। वे प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक परियोजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय के अवसर तलाशने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने भारत में फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं को स्वीकार किया।
- भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के दोनों नेताओं ने सितंबर 2023 में दिल्ली में **जी20 शिखर सम्मेलन** के मौके पर **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (आईएमईसी)** के शुभारंभ को याद किया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस ऐतिहासिक पहल में उनके नेतृत्व के लिए प्रधान मंत्री मोदी को बधाई दी। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि यह परियोजना अत्यधिक रणनीतिक महत्व की होगी और भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच वाणिज्य और ऊर्जा के प्रवाह की क्षमता और लचीलेपन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना के लिए राष्ट्रपति मैक्रों के विशेष दूत की नियुक्ति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने दक्षिण पूर्व एशिया से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक विभिन्न अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर पेरिस में जुलाई में हुए शिखर सम्मेलन में अपनी चर्चा को याद किया और विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की।

भारत - फ्रांस संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

- 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा न केवल एक राजनयिक रिश्तों के लिए मील का पत्थर है, बल्कि 2018 के बाद से मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विकसित हुई गहरी और व्यक्तिगत दोस्ती को भी रेखांकित करती है। यह यात्रा फ्रांस को भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के रूप में मजबूत करती है, और उनके सौहार्द की कहानी भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी का केंद्र बन गई है। शुरुआत से ही, दोनों नेताओं ने अपने राष्ट्रों के लिए साझा दृष्टिकोण और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।
- मैक्रों के सरकार चलाने की रणनीति पीएम मोदी से काफी हद तक मेल खाती है। यही कारण है कि वह 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। वह फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति और नेपोलियन III के बाद सबसे कम उम्र के राष्ट्र प्रमुख बने। मोदी और मैक्रों के बीच व्यक्तिगत केमिस्ट्री 2018 में उनकी भारत यात्रा के दौरान स्पष्ट हुई, जहां उन्होंने संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का शुभारंभ किया। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई इस पहल ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उनकी पारस्परिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।
- फ्रांसीसी विमान और हेलीकॉप्टर (आउरगन, मिस्टीरे, अलिज़े, अलौएट, जगुआर आदि) 1960 के दशक से ही भारत के हवाई बेड़े का हिस्सा रहे हैं।
- फ्रांस ने वाइकिंग और सेंटॉर रॉकेट प्रौद्योगिकियों को 1970 के दशक में भारत को साझा किया और फ्रांस ने भारत के श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्चर केंद्र की स्थापना में सहायता किया था।
- 1984 में, अमेरिका ने घरेलू कानूनी बाधाओं का हवाला देते हुए तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन प्रदान करने के एक समझौते से पीछे हट गए। उस समय फ्रांस ने भारत को परमाणु ईंधन की आपूर्ति में मदद की थी।
- भारत - फ्रांस रणनीतिक साझेदारी मजबूती से एक बहुध्रुवीय दुनिया में निहित है जो सुधार और सफल बहुपक्षवाद, रणनीतिक स्वायत्तता में दृढ़ विश्वास, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और इन सिद्धांतों में विश्वास पर निर्भर है।
- भारत - फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में दोनों पक्ष लोकतंत्र के सामान्य मूल्यों, बुनियादी स्वतंत्रता, कानून के शासन और मानवाधिकारों के सम्मान को बनाए रखने के लिए समर्पित हैं।
- फ्रांस के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी के मुख्य स्तंभ रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष अन्वेषण और असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग हैं।

सामरिक - रणनीतिक साझेदारी :



- हाल के वर्षों में हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-फ्रांस समुद्री सुरक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत अपनी बढ़ती आर्थिक, समुद्री सैन्य क्षमताओं और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ पूरे क्षेत्र के देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। दूसरी ओर, फ्रांस ने भू-राजनीतिक बदलावों को पहचानते हुए, एक इंडो-पैसिफिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की इच्छा पर जोर देना शुरू कर दिया है। हाल की भारत-फ्रांस द्विपक्षीय बातचीत में हिंद महासागर चर्चा का प्राथमिकता क्षेत्र बन गया है क्योंकि दोनों देश समुद्री क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक

साझेदारी का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। 22 अगस्त, 2019 को फ्रांस के पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 45 वीं जी7 शिखर बैठक के लिए फ्रांस की राजकीय यात्रा पर थे। द्विपक्षीय वार्ता के बाद, अन्य बातों के अलावा, हिंद महासागर में संयुक्त समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र (सीएनईएस) फ्रांस के बीच व्यवस्था लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह इसरो और सीएनईएस के बीच मार्च 2018 में हस्ताक्षरित पहले के समझौता ज्ञापन का अनुसरण करता है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर पर केंद्रित समुद्री निगरानी उपग्रह प्रणाली का सह-विकास करना है। ये समझौते आईओआर में समुद्री सुरक्षा के लिए भारत-फ्रांस सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

- फ्रांस और भारत के बीच 1998 में जब दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की तो इनके आपसी सामरिक रणनीतिक साझेदारी संबंध में व्यापक बदलाव हुए।
- इस सामरिक गठबंधन के तीन मुख्य स्तंभ सैन्य सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और असैन्य परमाणु सहयोग हैं।
- दोनों राष्ट्रों के बीच के रणनीतिक साझेदारी संबंधों में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दोनों ही देश वैश्विक राजनीतिक स्तर पर दो गुटों में ध्रुवीकृत होने के बजाय एक लोकतंत्रों द्वारा शासित एक बहुध्रुवीय दुनिया का पक्ष लेते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस ने भारत का लगातार समर्थन किया है।
- फ्रांस भी सभी चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं, अर्थात् ऑस्ट्रेलिया समूह, वासेनार व्यवस्था, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एजी) में भारत की सदस्यता का प्रबल समर्थक रहा है।
- डब्ल्यूए, एमटीसीआर और एजी में भारत की स्वीकृति फ्रांस की सहायता से संभव हुई।
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई दोनों ही देशों की प्राथमिकताओं में शामिल है।

आर्थिक - सहयोग :

- भारत और फ्रांस ने 2018 में अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2022 तक 15 बिलियन यूरो तक बढ़ाने और भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर "समय पर पुनः लॉन्च वार्ता" पर भारत और फ्रांस ने अपनी सहमति व्यक्त की है।
- फ्रांसीसी - भारतीय व्यापार, जो लगातार बढ़ रहा था, 2020 में COVID-19 संकट (2019 में € 11.5 बिलियन के विपरीत € 9 बिलियन) के परिणामस्वरूप काफी कम हो गया।
- फ्रांसीसी निर्यात का एक बड़ा हिस्सा संचार उपकरण, रसायन, और दवा और रासायनिक उद्योगों से बना है।
- फ्रांस भारत का 17वां सबसे बड़ा ग्राहक है और इसकी आपूर्ति करने वाले देशों में 1% बाजार हिस्सेदारी के साथ 27वें स्थान पर है।
- वर्तमान में 540 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां भारत के विभिन्न उद्योगों में सहायक के रूप में काम कर रही हैं और लगभग 300,000 लोगों को रोजगार दे रही हैं।
- भारत के 20 से अधिक शहरों में पहले से ही स्थायी शहरी विकास परियोजनाएं हैं जो फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसके साथ - ही - साथ भारत और फ्रांस "स्मार्ट सिटीज" कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक साथ काम कर रहे हैं।

असैन्य परमाणु सहयोग :

- 1950 में, फ्रांसीसी परमाणु ऊर्जा आयोग (सीईए) ने भारत को असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता की पेशकश की। इस प्रस्ताव को 1951 में तब और अधिक महसूस किया गया जब दोनों देशों ने "बेरिलियम-संचालित रिएक्टरों के अनुसंधान और निर्माण के लिए" आपस में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत के परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास को फ्रांस से बहुत लाभ हुआ है।
- 1974 में भारत के शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट की प्रशंसा करने वाला फ्रांस एकमात्र पश्चिमी देश था, जिसे परमाणु क्षेत्र में भारत की प्रगति के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया था।
- अमेरिका और कनाडा द्वारा 1974 के शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के विरोध में अपने समझौतों को समाप्त करने के बाद, भारत को अपना समर्थन देते हुए फ्रांस ने भारत के तारापुर परमाणु संयंत्र को ईंधन की आपूर्ति जारी रखी।

- 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों से असहमति जताई और आईएईए के साथ भारत की बातचीत के लिए एक अनुकूल वातावरण के निर्माण में अपना योगदान दिया।
- 30 सितंबर, 2008 को भारत और फ्रांस के बीच असैन्य परमाणु सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार, फ्रांस 9,900 मेगावाट जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना (JNPP) को तेजी से लागू करेगा और छह 1,650 मेगावाट यूरोपीय दबाव रिएक्टर (EPR) परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगा।

भारत - फ्रांस द्विपक्षीय व्यापारिक - संबंध :

- विगत 10 वर्षों में फ्रांस के साथ द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिसका 10.75 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- हाल ही में दोनों देशों के बीच करीब 16 अरब डॉलर के व्यापारिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- भारत और फ्रांस दोनों ही देश इस पर सहमत हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश समझौतों को तेजी से ट्रैक करना दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
- वर्तमान समय में लगभग 1,000 फ्रांसीसी कंपनियों की तुलना में सौ से अधिक भारतीय व्यवसायों ने फ्रांस में अपना व्यापार स्थापित किया है।
- भारतीय व्यवसायी अपने व्यवसाय को यूनाइटेड किंगडम में अपने व्यवसाय का होना यूरोप में अपने व्यवसाय को प्रवेश बिंदु के रूप में देखते थे। अब, ब्रेक्सिट के तेजी से आने के साथ, भारत - फ्रांस को भी एक विकल्प के रूप में मान रहा है।

भारत - फ्रांस रक्षा - संबंध :

- भारत और फ्रांस अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे अंतःक्रियाशीलता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं और संयुक्त बलों के सहयोग को बनाने के लिए आपस में चर्चा जारी रखते हैं।
- भारत और फ्रांस ने दोनों देशों के बीच पारस्परिक रसद आपूर्ति के समर्थन के प्रावधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है।
- भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के स्तंभों में से एक भारत और फ्रांस के बीच आपस में रक्षा औद्योगिक सहयोग रहा है।
- फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और भारत के प्रधान मंत्री मोदी दोनों ने पिछले समझौतों में विशेष रूप से राफेल लड़ाकू जेट की डिलीवरी पूरा करने में की गई फ्रांस की प्रगति की प्रशंसा की है।
- 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए, दोनों नेताओं ने रक्षा उद्योग में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने दोनों देशों की रक्षा कंपनियों के बीच मौजूदा और आगामी गठबंधनों को भी अपना समर्थन दिया।
- फ्रांस से भारत द्वारा खरीदे जाने वाले सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी रक्षा उत्पाद राफेल लड़ाकू विमान और पी-75 स्कॉर्पीन परियोजना हैं।
- भारत और फ्रांस के बीच आपस में तीन अलग-अलग सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है जिसमें शक्ति, वरुण और गरुड़ सैन्य अभ्यास शामिल है।
- फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत के रिलायंस समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम, डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड (DRAL) का महाराष्ट्र के मिहान नामक स्थान पर एक विनिर्माण उद्योग है।

भारत - फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग :

- फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, सीएनईएस, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रमों और उपग्रह प्रक्षेपणों का एक लंबा इतिहास है, जो पचास साल पुराना है।
- भारत और फ्रांस दोनों ने 2018 में "अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त दृष्टिकोण" जारी किया, जो नागरिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनके साझा ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित था।
- जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करते हुए, जहां दोनों पक्ष संयुक्त मिशन मेघा-ट्रॉपिक्स और सरल-अल्टिका पर जलवायु निगरानी के लिए अपना सहयोग जारी रखेंगे, भूमि इन्फ्रारेड निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह का चल रहा शोध, और ओशनसैट 3-आर्गोस मिशन।

- फ्रांस और भारत द्वारा गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, सीएनईएस, वैज्ञानिक प्रयोग योजनाओं के विकास का समर्थन करेगी और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को फ्रांसीसी उपकरण, आपूर्ति और चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति करेगी।
- 2022 तक भारत के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चिकित्सा सहायता कर्मियों को प्रशिक्षित करने के विकल्प की प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन दोनों ने प्रशंसा की।

जलवायु – परिवर्तन के प्रति भारत और फ्रांस का दृष्टिकोण :

- भारत और फ्रांस दोनों ही देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ और पर्यावरण – संरक्षण को बढ़ावा देने में आपस में एक – दूसरे के प्रति आपसी सहयोग को बढ़ा रहे हैं।
- एजेंस फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट (AFD) जो वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के संरक्षण के लिए समर्पित एक मिशन है के साथ फ्रांस ने वर्ष 2008 से ही भारत में काम करना शुरू कर दिया है।
- सीओपी21 के दौरान नवंबर 2015 में सौर ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के तहत भारत और फ्रांस दोनों ही देशों ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है।
- फ्रांस और भारत द्वारा साझा की जाने वाली प्राथमिकताओं में नीली अर्थव्यवस्था और तटीय लचीलापन शामिल हैं। वे समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान और महासागरों के बारे में अपनी समझ में भी अपना आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

नीली अर्थव्यवस्था :

- “ब्लू इकोनॉमी” शब्द आर्थिक विकास, बढ़ी हुई आजीविका और रोजगार के अवसरों, और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महासागर संसाधनों और महासागर विकास पहलों के सतत उपयोग को संदर्भित करता है।
- यह एक समावेशी ढांचा प्रदान करता है जो तटीय देशों को सभी लोगों के लिए समुद्री संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की भी पुष्टि करता है, विशेष रूप से SDG14, “पानी के नीचे का जीवन।”
- यह विचार ज्यादातर पर्यावरणीय खतरों और महासागरीय पारिस्थितिक कमी को कम करते हुए सामाजिक न्याय और मानव कल्याण में सुधार पर केंद्रित है।



भारत और फ्रांस के बीच आपसी सांस्कृतिक सहयोग :

- भारतीय संस्कृति के प्रति फ्रांस के नागरिकों और फ्रांसीसी लोगों में गहरी आस्था है।
- अपनी-अपनी संस्कृतियों को बढ़ावा देने के प्रयास में, भारत और फ्रांस सह-मेजबान त्योहार: नमस्ते फ्रांस ने 2016 के अंत में फ्रांस में भारत को प्रदर्शित किया, जबकि बोनजोर इंडिया 2017 के अंत और 2018 की शुरुआत में भारत में आयोजित किया गया था।

- पेरिस बुक फेयर 2021 में एक विशेष अतिथि के रूप में फ्रांस में भारत के द्वारा मेजबानी की गई , जबकि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 में भारत में फ्रांस ने मेजबानी किया।
- श्री ए.एस. किरण कुमार को फ्रांस – भारत अंतरिक्ष सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए , फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है।
- जीनस्टोर, एक भारतीय-आधारित डायग्नोस्टिक्स कंपनी, को फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ निवेश के रूप में मान्यता दी गई है।
- सौमित्र चटर्जी, जो एक भारतीय हैं , को फ्रांस का सर्वोच्च कलात्मक सम्मान दिया गया है।

भारत और फ्रांस के बीच आपस में शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग :

- भारत और फ्रांस के बीच हल के वर्षों में आपस में द्विपक्षीय शैक्षिक सहयोग में उतरोत्तर वृद्धि हुई है। भारत और फ्रांस के विश्वविद्यालयों और निजी संगठनों ने आपस में लगभग 300 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च (CEFIPRA), जो 25 वर्षों से परिचालित है, मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, सीमांत प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिकों और पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान में सीमा पार वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- फ्रांसीसी और भारतीय दोनों विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान अपने तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं। भारत और फ्रांस ने आपस में "रमन-चारपाक फेलोशिप" की शुरुआत किया है, जो दोनों देशों के डॉक्टरेट छात्रों के आदान-प्रदान की अनुमति देगा।
- छात्रवृत्ति कार्यक्रमों और भारतीय और फ्रांसीसी शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग द्वारा समर्थित, 2025 तक 20,000 के लक्ष्य के साथ 2019 में 10,000 भारतीय छात्रों को फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में नामांकित किया गया है।
- भारत और फ्रांस ने आपस में शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (EEP) की शुरुआत की है। जिसमें डिग्री की पारस्परिक मान्यता, अनुसंधान कार्यक्रम को मजबूत करना और एक लचीली वीजा व्यवस्था के माध्यम से छात्र – विद्वान अनुसंधान गतिशीलता को बढ़ावा देना शामिल है, द्विपक्षीय शैक्षिक सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 . भारत – फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन की भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है और गणतंत्र दिवस के सम्माननीय अतिथि के रूप में किसी फ्रांसीसी नेता की दसवीं यात्रा है।
2. भारत और फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण की परस्पर जुड़ी चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
3. भारत और फ्रांस वर्ष 2024 में अपने आपसी रणनीतिक साझेदारी का 25वां वर्षगांठ मना रहा है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

- (A). केवल 1 और 2
- (B). केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3।
- (D). इनमें से सभी।

उत्तर – (B)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q.1. " भारत – फ्रांस द्विपक्षीय बातचीत में हिंद महासागर चर्चा का प्राथमिकता क्षेत्र बन गया है क्योंकि दोनों देश समुद्री क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं।" इस कथन के आलोक में भारत – फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न आयामों की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

Akhilesh kumar shrivastav